साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 24 मई 2021, वर्ष-7, अंक-08

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

- अब चयन की आयु सीमा 40 से घटाकर 25 वर्ष की गई
- आवेदन लेने के छह महीने बाद मप्र सरकार ने लिया निर्णय
- 2020 में कमलनाथ ने सभी की सेवाएं कर दी थीं समाप्त

प्रदेश के 52 हजार गांवों में फिर तैनात होंगे 'कृषक मित्र'

अरविंद मिश्र, भोपाल

डेढ़ दशक बाद मप्र की सत्ता में आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जनवरी 2020 में आठ साल से सेवारत 26 हजार कृषक मित्र और दीदी की सेवा समाप्त कर दी थी। लेकिन मार्च 2020 में जैसे ही शिव-राज आया वैसे ही सरकार को कृषक मित्रों की याद आई। छह माह पूर्व कृषक मित्रों से लिए गए आवेदनों पर अब आयु सीमा की नई शर्त और नए मानदेय के साथ सरकार ने भर्ती की मंजूरी दी है। एक बार फिर मप्र के 52 हजार गांवों में 26 हजार कृषक मित्रों की तैनाती की जाएगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुराने आवेदकों के आवेदन मान्य होंगे या उन्हें फिर आवेदन करना पड़ेगा। चूंकि पहले आवेदकों में अधिकांश हटाए गए कृषक मित्र और दीदी ही थीं। गौरतलब है कि हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार की कृषि विस्तार योजना के तहत प्रदेश में कृषक मित्र चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा अब 40 की जगह 25 वर्ष होगी। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

फरवरी में लिए थे आवेदन

सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्स्टेंशन आत्मा अंतर्गत किसान मित्र के चयन के लिए आवेदन पत्र 15 फरवरी 2021 तक आमंत्रित किए गए थे। कृषक मित्र के लिए शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल पास, दो ग्रामों में से किसी एक ग्राम का निवासी होना अनिवार्य है। चयनित कृषक मित्र से भविष्य में शासकीय सेवक का दावा नहीं करने का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र भी लिया गया था।

2012 में हुई थी भर्ती: कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के 26 हजार कृषक मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दीं। इन सभी को आठ साल पहले शिवराज सरकार में रखा गया था। इनकी नियुक्ति 2012 में हुई थी।

इनका क्या होगा: इधर, नौकरी की तय आयु पार कर चुके कृषक मित्र व दीदी बेकाम हो गए। उन्हें उम्मीद थी की सरकार इनके काम को देखते हुए भर्ती में इन्हें प्राथमिकाता देगी। लेकिन अब अप्रशिक्षितों की भी भर्ती के आवेदन मांगे गए हैं। जबकि इन्हें पिछले आठ साल में इतना दक्ष कर दिया कि इन्हें प्रशिक्षण की जरूरत ही नहीं।

कृषक मित्र कृषि के साथ अन्य अनुषांगिक विभागों व किसानों के मध्य कार्य करेंगे। मप्र के 52 हजार गांव में 26 हजार कृषक मित्र बनाए जाएंगे। दो गांव के मध्य एक कृषक मित्र का चयन किया जाएगा। हमने सीएम के नेतृत्व में कैबिनेट में आत्मा परियोजना अंतर्गत कृषक मित्रों के चयन की न्यूनतम आयु सीमा को 40 से घटाकर 25 वर्ष करने का निर्णय लिया है। जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे अब हमारे स्थानीय युवा साथियों को मौका मिलेगा।

कमल पटेल, कृषि मंत्री, मप्र

डीएपी खाद पर सरकार देगी 140 फीसदी सब्सिडी

किसानों का दिल बाग-बाग

भोपाल/ नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के साथ देशभर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 140 फीसदी बढ़ा दी है। अब किसानों को प्रति बोरी 500 रुपए की जगह 1200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को 2,400 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए कीमत चुकानी होगी। इसका मतलब है कि अब उन्हें पुरानी कीमत पर ही डीएपी मिलेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि **'जागत गांव हमार'** ने डीएपी की बढ़ी कीमतों और किसानों की समस्या को लेकर प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की थी।

केंद्र पर अतिरिक्त बोझः डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने के फैसले से अब केंद्र सरकार पर अतिरिक्त करीब 14,775 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद देशभर के किसानों को पुरानी दरों पर ही डीएपी खाद मिलनी चाहिए।

फॉस्फोरिक एसिड-अमोनिया महंगा

पिछले साल डीएपी 1,700 रुपए प्रति बोरी थी। इस पर केंद्र सरकार 500 रुपए की सब्सिडी देती थी। इस तरह किसानों को प्रति बोरी 1200 रुपए की कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन, हाल में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की कीमतें 60 से 70 फीसदी तक बढ़ गई हैं। इसके चलते डीएपी की एक बोरी की कीमत 2,400 रुपए हो गई है। सब्सिडी घटाकर खाद कंपनियों को इसकी बिक्री प्रति बोरी 1900 रुपए में की जाती है।

किसानों को बड़ी राहत

केंद्र सरकार के फैसले के बाद किसानों को डीएपी के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। उन्हें प्रति बोरी 1200 रुपए में डीएपी मिलती रहेगी। केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी के रूप में 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है।

किसानों की सरकार

इधर, डीएपी खाद पर सब्सिडी 140 फीसदी सदी बढ़ाने जाने पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि मप्र के किसानों की ओर से पीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का बहुत बड़ा किसान हितैषी निर्णय लिया है। डीएपी खाद का एक बैग 2400 की जगह 1200 रुपए में ही मिलेगा। भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है।

- अब खाद के लिए नहीं चुकानी होगी ज्यादा कीमत
- बढ़े भाव के बीच मोदी सरकार ने खोला खजाना
- केंद्र पर 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा
- अभी सब्सिडी पर सालाना 80,000 करोड़ था खर्च

डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बोरी से 140 फीसदी बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। डीएपी की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद, इसे 1200 रुपए के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है। मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री द्वारा खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक किसान हितैषी निर्णय लिए जाने का मैं स्वागत करता हूं। खाद सब्सिडी को 140 फीसदी बढ़ाकर अब 1200 रुपए प्रति बैग किया गया है। किसानों को डीएपी खाद का एक बैग 2400 के बजाय अब 1200 रुपए में ही मिलेगा। मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

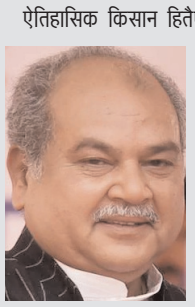

नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री

प्रधानमंत्री का संकल्प किसानों की आय दोगुनी करना है। उसके लिए लागत घटाना सबसे बड़ा उपाय है। केंद्र ने जो सब्सिडी बढ़ाई है, उसमें साढ़े 14 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। मैं मध्यप्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं। अब 2400 रुपए की डीएपी की बोरी किसानों को 1200 रुपए में मिलेगी।

शिवराज सिंह चौहान, सीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, यह निर्णय मप्र के साथ देशभर के किसानों को राहत देगा। यह चिंतन जरूर होना चाहिए कि केंद्र सरकार में वे कौन सलाहकार हैं, जो किसान-विरोधी निर्णय लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि खेती को लेकर सरकार संवेदनशील रहेगी। खाद और बीज को लेकर अब ऐसा कोई भ्रम पैदा ही नहीं होगा, जो किसानों को चिंतित करे।

जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री

देश के प्रधानमंत्री ने हमारे अन्नदाताओं के हित को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इस संवेदनशील निर्णय के लिए देशभर के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार। सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद, राज्य सभा

सावधान! मप्र में हो सकता है खाद का संकट

इधर, मध्य प्रदेश में किसानों के सामने खाद का संकट आने के आसार हैं। जबलपुर, रीवा, मंदसौर, रायसेन, शिवपुरी समेत कई जिलों में 1200 की डीएपी खाद की बोरी 1900 रुपए में मिल रही है। जबकि बोरियों पर पैकिंग दिसंबर 2020 अंकित है। कंपनियों से सरकार ने कम कीमत के दौरान ही एक लाख टन डीएपी और 10 हजार टन एनपीके खरीद लिया था, लेकिन जरुरत 10 लाख टन से ज्यादा की है। अभी किसान फसल के लिए खेतों में तैयारी कर रहे हैं। उन्हें खाद की जरुरत 25 मई के बाद से होगी। खाद की मांग जून से तेजी पकड़ सकती है। तब खाद के लिए संकट की स्थिति निर्मित होने की आशंका है। प्रदेश में अगले माह करीब साढ़े 9 लाख टन खाद की जरुरत पड़ेगी। खुले बाजार की हालत ठीक नहीं है, तो खाद को लेकर संकट की स्थिति बन सकती है। गौरतलब है कि पिछले साल प्रदेश में सरकारी और खुले बाजार से 10 लाख टन खाद की आपूर्ति हुई थी। इस साल सरकार ने एक लाख 18 हजार टन डीएपी खाद की व्यवस्था कर ली है। इसके बाद छह से साढ़े छह लाख टन खाद की जरुरत होगी। खुले बाजार में भी तीन लाख टन की आपूर्ति अलग से होगी।

स्टॉक में 1.18 लाख टन, मांग 10 लाख टन

इनका कहना है

मप्र में खाद की उपलब्धता को लेकर मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। किसानों के पास आगामी फसल के लिए अपने खेतों को तैयार करने और खाद बीज आदि की व्यवस्था करने के लिए सिर्फ एक महीना बचा है। ऐसे में रासायनिक उर्वरक को सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे किसानों के घर तक पंहुचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दिग्विजय सिंह, पूर्व सीएम

- प्रदेश में इस बार 25 मई से 2 जून तक रहेगा नौ तपा
- दस साल में पहली बार दिन का पारा सबसे ज्यादा तपेगा
- औसत तापमान भी 44 डिग्री सेल्सियस पार हो जाएगा
- शुरू में तपने के कारण शेष दिनों में बारिश की संभावना
- 2018 ही ऐसा साल रहा जब नौतपा में तपिश ज्यादा रही
- इंदौर जिले में जून और जुलाई में सामान्य बारिश का दावा

मप्र में खूब तपेगा नौ-तपा

विशेष संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में इस बार नौ तपा खूब तपेगा। इतना ही नहीं, बीते 10 साल में पहली बार औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। इन सालों में अधिकतम पारा अब तक 44 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाया है। अगर ऐसा हुआ तो वर्ष 2012 के बाद पहली बार नौ तपा में इतनी गर्मी होगी। मौसम विभाग इसका कारण साइक्लोन का जल्दी आना बता रहा है। इस बार 25 मई से 2 जून तक नौ तपा रहेगा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि इस बार 25 मई से दो जून तक गर्मी ज्यादा रहेगी। शुरुआती दिनों में यह 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। नौ तपा के समय अक्सर साइक्लोन आते हैं। इस कारण कई सालों से नौ तपा उतने नहीं तपे। वर्ष 2015 के बाद वर्ष 2018 और 2019 में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा था।

मई में दो साइक्लोन आए

इस साल मई में अब तक दो साइक्लोन आ चुके हैं। इस कारण इस बार नौ तपा में तापमान बढ़ेगा। पहले तीन दिन में ही तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इससे बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। पहले सिस्टम और फिर लोकल गतिविधियों से बारिश हो सकती है।

साइक्लोन का प्रभाव

अप्रैल और मई साइक्लोन सीजन होते हैं। हर महीने एक-दो साइक्लोन आते ही हैं। अरेबियन सी में कम बनते हैं, लेकिन इस बार यहां मजबूत साइक्लोन बन रहे हैं। इसके अलावा वे ऑफ बंगाल में भी साइक्लोन बन रहा है। दोनों सिस्टम पहले ही आ गए। इससे बारिश होने के कारण तापमान उतना नहीं बढ़ पाया। अब कोई साइक्लोन नहीं होने के कारण एक-दो दिन बाद तापमान बढ़ेगा। इस महीने 24 मई से तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी होगी।

पछले साल तपा था खजुराहो

पिछले वर्ष की बात की जाए तो नौ तपा में मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान खजुराहो में ही 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि अन्य शहरों यह इससे कम ही रहा था। इस कारण प्रदेश का औसत तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस था। इससे कम वर्ष 2013 और 2016 में था।

भोपाल में बारिश के आसार

इधर, भोपाल में इस बार नौतपा में शहर में मौसम मिलाजुला रहने के आसार हैं। शुरुआती 4-5 दिन तपिश ज्यादा रहेगी, लेकिन बाद में मौसम के तेवर नरम पड़ सकते हैं। इस दौरान बारिश के आसार भी बनेंगे। शहर में नौतपा का ट्रेंड भी कुछ ऐसा ही है। बीते 9 साल में तीन बार 2015, 2018 और 2019 में ही नौतपा में औसत तापमान 43 डिग्री पार रहा था। बाकी 6 सालों में औसत तापमान 43 डिग्री तक भी नहीं पहुंच सका। मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक ने बताया कि ट्रेंड के अनुसार इस बार 25 मई से 2 जून तक शुरुआत में तापमान ज्यादा रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम बदलने के कारण तापमान में कमी आ सकती है।

9 सालों में नौतपा का तापमान

2012	42.7 डिग्री
2013	41.2 डिग्री
2014	42.3 डिग्री
2015	43.1 डिग्री
2016	41.1 डिग्री
2017	41.6 डिग्री
2018	43.7 डिग्री
2019	43.6 डिग्री
2020	41.4 डिग्री

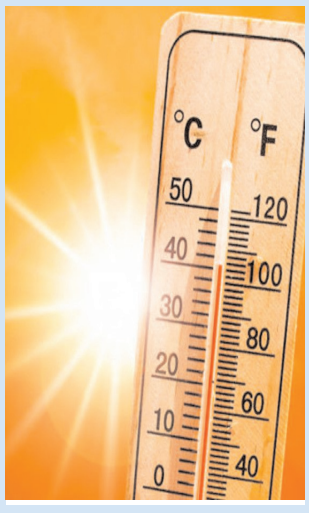

इंदौर में नहीं दिखाई देगी सूरज की तपन

इंदौर में इस बार नौतपता में सूरज नहीं तपेगा और ज्यादा गर्मी नहीं होगी। वर्तमान में अरब सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से अरब सागर से इंदौर की ओर नमी आएगी। नौतपा के पहले सप्ताह में 25 मई के बाद इंदौर व उज्जैन में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस बार नौतपा में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने की संभावना है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून जून के पहले सप्ताह में दस्तक देगा। ऐसे में इस बार मध्य प्रदेश व इंदौर संभाग में 15 से 20 जून के बीच मानसून का प्रवेश होने होने की संभावना है। जिसे देखते हुए मप्र के किसानों ने अपने खेतों को बोवनी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है।

2016 में सबसे कम तपिश

पिछले नौ साल में 2016 में नौतपा सबसे ज्यादा तपा था। तब औसत तापमान 41.1 डिग्री था। 2018 में नौतपा में दिन का औसत तापमान 43.7 डिग्री रहा था। यह साल देशभर में भी सबसे गर्म वर्षों में गिना जाता है।

चार बार पारा 45 पार पहुंचा

इन 9 सालों में नौतपा के दिनों में सिर्फ चार बार ही पारा 45 डिग्री पार पहुंच सका। 2015 में 31 मई को दिन का तापमान 45.4, 2018 में 27 मई और 29 मई को तापमान 45.3 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके बाद 2017 में भी 27 मई को तापमान 45.1 डिग्री रहा था।

अगस्त माह में होगी झमाझम बारिश

मौसम वैज्ञानियों के मुताबिक यह लगातार तीसरा साल है जब मानसून के पहले अरब सागर में चक्रवती तूफान बन रहा है। इसके कारण मप्र में प्री मानसून में ही बारिश होने की संभावना है। इस साल मानसून के चार माह में इंदौर संभाग में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर में जून और जुलाई में सामान्य बारिश होगी। वहीं मप्र में अगस्त में सामान्य से तीन प्रतिशत अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है।

सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में परिभ्रमण काल

ऐस्ट्रॉलजर और वास्तु एक्सपर्ट सचिन मेहरा बताते हैं कि सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में पररिभ्रमण काल 14 दिनों का है। इस काल के शुरू के नौ दिनों को नौतपा कहते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बार नौतपा के शुरुआती छह दिनों में गमीज़ के साथ ही उमस भी खूब होगी। वहीं जब नौतपा समापन की ओर होगा तब अंतिम के तीन दिन हवाएं तेज चलेंगी। कहीं-कहीं मध्यम बारिश के भी आसार हैं तो कहीं बौछारे भी पड़ सकती हैं।

इसलिए महत्वपूर्ण नौतपा

सनातन धर्म में सूर्य देवता का विशेष स्थान है। नौतपा का वर्णन श्रीमद्भागवत में भी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जब ज्योतिष की रचना हुई तबसे ही नौतपा भी चला आ रहा है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होकर वृषभ राशि के 10 से 20 अंश तक रहते हैं तब नौतपा होता है। इस नक्षत्र में सूर्य करीब 14 दिनों तक मौजूद रहेंगे। लेकिन शुरुआती 9 दिनों में कफी गर्मी होती है। यही वजह है कि इन दिनों को नौतपा कहते हैं।

मंत्री बोले: जन-सहयोग से टेमा गौ-अभ्यारण्य होगा विकसित, कमल पटेल ने सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य केंद्र का किया दौरा

सड़क पर गाय को नहीं रहने देंगे, अभ्यारण में होगी देखभाल

संवाददाता, भोपाल

यह मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में एक जन सहयोग से सरकार के सम्मिलित से एक बहुत अच्छा गौ-अभ्यारण्य यहां पर हरदा जिले में शुरू हो गया है। गौ-माता की रक्षा हो जाएगी। गौ-माताएं पल जाएंगी तो इससे अधिक मात्रा में यहां गौ-मूत्र से दवाइयां जैविक खाद उपलब्ध हो सकेगा। आज रासायनिक खाद दवाई के उपयोग होने के कारण जो मिट्टी जहरीली हो रही है। किसानों को खेती में लागत भी कम लगेगी, गौ-माता की रक्षा भी होगी। खेती भी जैविक होगी और गौ आधारित खेती के साथ गौ आधारित उद्योग और खेती आधारित उद्योग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी पूर्ण होगा। यह बात प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सतपुड़ा गौ-अभ्यारण्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान कही। इसी दौरान मंत्री ने गायों के हित को देखते हुए कलेक्टर संजय गुप्ता, जिला सीईओ आरके शर्मा, एडीएम जेपी सैय्याम, एसडीएम तहसीलदार जनपद सीईओ, डीएफओ पंचायत सचिव को बुलाकर मीटिंग बुलाई। जिसमें गांव के लोगों को भी शामिल किया गया। ग्राम सभा में मंत्री ने कलेक्टर सीईओ डीएफओ को निर्देशित किया, कि जल्द से जल्द नियमानुसार यहां गौ माताओं के लिए शेड और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं।

किसानों ने भेंट की मूंग

इधर, कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिला हरदा में किसानों ने प्रतीकात्मक रूप से मूंग की फसल कृषि मंत्री कमल पटेल को भेंट की। इस वर्ष भी कोरोना कर्फ्यू के असाधारण समय में तवा डैम से मूंग की फसल में पानी छोड़े जाने से हरदा में 1.25 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल हुई है। इससे किसानों, मजदूरों, खाद, बीज, दवाई के दुकानदारों आदि को लाभ हुआ।

सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित

मंत्री कमल पटेल ने धरती माता, देश समाज, गौ-माता के हित में 10 मिनट में निर्णय लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया, कि सतपुड़ा गौ-अभ्यारण्य स्थल पर ही गौ माताओं के लिए पूर्ण व्यवस्था की जाए। जिसके लिए प्रशासन को निर्देशित किया। अब यहां शेड बन जाएंगे और गौ-माताओं की भी रक्षा होगी, क्योंकि बाउंड्रीवाल हो जाएगी और यहां जब गौ माता रहेंगी तो लोगों का आना जाना रहेगा, तो लकड़ी चोरी भी नहीं होगी। फिलहाल प्रशासन की देखरेख में 2 पंचायतें कपासी और टेमागांव के सामुदायिक भवन बनाने का कार्य प्रारंभ होगा। गौरतलब है कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर संकल्प लिया था, कि जनता के सहयोग से हरदा जिले की सड़कों पर गाय को नहीं रहने देंगे। उनके लिए गौ-अभ्यारण्य बनाएंगे।

समर्थन मूल्य पर अब मप्र सरकार पांच जून तक खरीदेगी चना

दो संभाग को छोड़कर बाकी जिलों में जारी रहेगी गेहूं की खरीदी

शिव राज में आहत किसानों को राहत

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में चने के समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख मप्र सरकार ने बढ़ा दी है। किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर चने की खरीद तारीख पांच जून तक कर दी है। गौरतलब है कि 15 मई को चने के समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो गई थी। एक चर्चा के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि हमें पता चला है कि कुछ जिलों में चना न्यूनतम मूल्य से नीचे गया है।

जिसके बाद किसानों ने सरकार से समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। इस पर फैसला लेते हुए ये तारीख पांच जून तक बढ़ा दी है। साथ ही संबंधित विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही खरीदी शुरू की जाए। सीएम ने कहा कि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रदेश में किसी भी किसान का चना समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देंगे। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी की अंतिम तिथि 05 जून तक बढ़ा दी गई है। किसान पांच जून तक समर्थन मूल्य पर अपना चना बेच सकते हैं। प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार।

ताऊते से खरीदी प्रभावित

इधर, चक्रवाती तूफान ताऊते के कारण प्रदेश में हो रही बारिश का असर गेहूं खरीदी पर भी पड़ा है। कई जिलों में झमाझम बारिश होने के कारण गेहूं की खरीदी नहीं हो पाई है। कई जगह पर गेहूं गीला होने और गीला गेहूं की खरीदी नहीं होने को लेकर अब किसान परेशान हैं तो वहीं राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर गेहूं की खरीदी के निर्देश दिए हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग में तय लक्ष्य तक खरीदी पूरी होने के बाद दूसरे संभागों में गेहूं खरीदी को जारी रहेगी।

दोबारा किसानों को भेजो मैसेज

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसानों को इस बात का भरोसा दिलाएं कि उनका पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। विभाग ने निर्देश दिए हैं 19 मई तक जिन किसानों को गेहूं खरीदी के लिए मैसेज भेजे गए थे और उनकी गेहूं खरीदी नहीं हो पाई है। उन्हें दोबारा मैसेज भेजकर गेहूं खरीदी की जाए। किसानों को भरोसा दिलाया जाए कि गेहूं की खरीदी को जारी रखा जाएगा।

पिछले साल हुई थी रिकॉर्ड खरीदी

बीते साल मप्र ने रिकॉर्ड एक करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी करके देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष भी अभी तक एक करोड़ 8 लाख 173 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा जा चुका है। इससे किसानों के खाते में 21 हजार 334 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में जाएंगे। अभी तक एक हजार 522 करोड़ राशि किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। प्रदेश में 4660 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं।

कमलनाथ ने उठाया था मुद्दा

गेहूं खरीदी के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया था और इस बात को लेकर सरकार से मांग की थी कि किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जाए। कमलनाथ ने कहा था कि खरीदी केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए लाइन में लगे किसानों का गेहूं गीला होने और उसकी खरीदी नहीं होने को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुले में रखे गेहूं का समय पर परिवहन नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाया था।

जारी रहेगी खरीदी

इधर, मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में गेहूं खरीदी को फिलहाल जारी रखने का आदेश जारी किया है। पहले जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में 25 मई तक गेहूं की खरीदी करना तय किया गया था, लेकिन अब विभाग के आदेश के बाद गेहूं की खरीदी 25 मई के बाद भी जारी रहेगी, जो किसानों के लिए राहत भरी खबर है।

जैव विविधता और कृषिः जियो और जीनो दो के सिद्धांत को देना होगा बढ़ावा

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर विशेष

डॉ. एमके भार्गव, वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ. पुष्पेंद्र सिंह, वैज्ञानिक, रा.वि.सिं.कृषि विवि, कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी, डॉ. कीर्ति गुप्ता, वरिष्ठ अध्यापक (जैवविविधता), शा- मॉडल उ.मा- विद्यालय शिवपुरी

जैवविविधता के परिप्रेक्ष्य में वैदिक काल में सोच बहुत व्यापक, सहिष्णतापूर्ण और भावनात्मक थी। वह सभी जीव-जंतुओं के कल्याण की कामना करते थे। परवतीकाल में जैव विविधता को संरक्षित और संवर्धित करने की प्रक्रिया में परिष्कार आया।

सभी जीवों पर दया तथा प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करने की अवधारणा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अंग रही है। जैवविविधता के परिप्रेक्ष्य में वैदिक काल में सोच बहुत व्यापक, सहिष्णतापूर्ण और भावनात्मक थी। वह सभी जीव-जंतुओं के कल्याण की कामना करते थे। परवतीकाल में जैवविविधता को संरक्षित और संवर्धित करने की प्रक्रिया में परिष्कार आया। विभिन्न प्रकार के जीव-जंतुओं और वनस्पतियों को धर्म से जोड़कर विभिन्न देवी-देवताओं को इनसे अंतसंबंधित कर दिया गया। स्मृतिकाल में बड़े-बड़े उद्यान लागाए जाने की प्रथा आरंभ हुई। पौधरोपण और जीव-जंतुओं को पानी पीने के लिए तालाब और जलाशय बनवाना धार्मिक पुण्य का कार्य माना जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जैवविविधता के संरक्षण के लिए खेती के लिए अनुपयोगी जमीन में जैविक उद्यान बनाए जाने का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार दो कोस परिणाम में मृगवन बनवाने का विधान है। इसमें स्वादिष्ट फल, लता, गुल्म और वृक्ष हों। पीपल, गूलर, पाकड़, आम और बरगद यह पंच पल्लव के रूप से जाने जाते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति जैवविविधता संपन्न क्षेत्र में आती है। समशीतोष्णीय जलवायु होने के कारण इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जैविक विविधता पायी जाती है। हिमालय पर्वत को विश्व का सर्वाधिक जैवविविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। कृषि योग्य अनेक फसलों का उद्गम इसी क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा अनेक जड़ी-बूटियों का विशाल भंडार हिमालय में विद्यमान रहा है। वास्तव में प्रारंभ में विभिन्न फसलों का उद्गम पृथ्वी के कुछ निश्चित क्षेत्र में हुआ था। इन क्षेत्रों को उद्गम केंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्रों की अवधारणा सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक बेवीलोव ने की थी। इनके अनुसार विश्व में 8 मुख्य उद्गम केंद्र हैं। जिसमें एक चीन-सोयाबीन, मूली, ब्रैसिका, नाशपाती, आड़ू, संतरा आदि। दो हिंदुस्तान- धान, अरहर, चना, लोबिया, मूंग, बैगन, भारतीय मूली, गन्ना, कपास, मिर्च, आम, नारियल, केला, हल्दी, आदि। तीन मध्य एशिया या अफगानिस्तान-गेहूं, सेम, अलसी, तिल, कुसुम, कपास, गाजर, खरबूज, प्याज, लहसुन, पालक, पिस्ता, अंगूर, सेब, बादाम आदि। चार भू-मध्य सागरीय-गेहूं जई, जौ, मटर, मसूर, गोभी शामिल है। पांच एबीसिनियां-ज्वार, बाजरा, अरंड, काफी, जौ, गेहूं, खेसारी, भिंडी आदि। छह फारस-लूर्सन, गाजर, पत्तागोभी, सलाद, अंजीर, अनार और सेव। सात मध्य अमेरिका-मक्क, राजमा, खीरा, शकरकंद, अरारोट, कपास, पपीता, अमरूद आदि और आठ में दक्षिणी अमेरिका-आलू, मूंगफली, अनन्नास, तम्बाकू, टमाटर, रबर, कुनैन, कसावा आदि शामिल है। जिसके स्त्रोत प्राचीन भारत में कृषि ज्ञान-डॉ. अनिल कुमार पांडेय व अन्य, भा.कृ.अनु.प- कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय नई दिल्ली प्रकाशन पृष्ठ संख्या 50 है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत कृषिजन्य फसलों के उद्गम का ,एक प्रमुख केंद्र रहा है। खाद्यान्नों की फसलों के अलावा कई जड़ी-बूटियों, पुष्पों-फलों और सब्जियों की भी उत्पत्ति इसी क्षेत्र से हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायवीय विविधता संभवत: जैवविविधता का मुख्य कारण रही है। हिमालय से कन्याकुमारी और हिंदुकुश से कामरूप तक विस्तृत इस महाद्वीप में जैव विविधता का प्रचुर भंडार रहा है। जैवविविधता संरक्षण एवं पर्यावरणीय प्रबंध एक-दूसरे के पर्यायवाची समझे जा सकते हैं। 'वसुधैव कुटम्बकम की भावना एवं जियो और जीनो दो' का सिद्धांत की अनुकरणीय पहल के साथ विकास की गति को बढ़ाना होगा। एक तरफा दबाव, हमेशा हानिकारक होता है। प्राकृतिक संसाधनों जल-जमीन, जंगल और जनता के समन्वय के साथ ही विकास की गति करना होगी। यहां मानवीय दृष्टिकोण केवल, एकल सोच न होकर प्राकृतिक संसाधनों के कुशल संरक्षण, संवर्धन बनाए रखने के लिए भू-आवरण पर चाहे वनाच्छादन हो या जल का कुशल दक्षतापूर्ण उपयोग आवश्यकता सीमित और संरक्षण की गति को बढ़ावा देना जरुरी है। पर्यावरणीय संतुलन चक्र/तंत्र में संतुलित स्थिति निर्मित बनी रहे या बनाई जा सके। ऐसी पहल के साथ जैवविविधता संरक्षण आयामों का बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस को मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 22 मई 1992 को नैरोबी में जैवविविधता पर अभिसमय के पाठ को स्वीकार किया गया था। इसलिए 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में जैवविविधता के महत्व के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस की थीम हमारे समाधान प्रकृति में है। वर्तमान युग में मनुष्य ने प्रकृति से दूर जाना प्रारंभ कर दिया है। आधुनिकता और शहरीकरण के अंधानुकरण के दवाब में हमने खुद को प्रकृति से दूर कर दिया है। विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ का खेल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पेड़ों की जगह गगन चुंबी इमारतों ने ले ली। हाइवे और फ्लाइओवर के चक्कर में हजारों पेड़ काटे गए। हमने नीम, पीपल और बरगद के पेड़ हटाकर फैशनेबल पेड लगाने आरंभ कर दिए। बगर यह सोचे कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।हम आधुनिकता की दौड़ में इस कदर शामिल हो गए कि अपने भारतीय मूल्यों को भूलते चले गए। हमारे पेड़ों और प्रकृति से प्राचीनकाल से एक अनुराग रहा है। हमारे समाज में प्रकृति को भगवान मानकर पूजने की परंपरा रही है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में पौधों और वृक्षों को लेकर कई मान्यताएं रही हैं। पीपल, वर और तुलसी को हमारे धर्म में आदिकाल से पूजा जा रहा है। हिदूं धर्म में हर त्यौहार प्रकृति से जुड़ा हुआ जैसे आज भी नागपंचमी के दिन बेरिया और वाहमी की पूजा की जाती है। नाग देवता को दूध अर्पित किया जाता है। श्रावण के महीने में राखी के त्यौहार के अगले दिन जौ के भुजरिया की पूजा की जाती है फिर आपस में वितरित कर प्रेम ,एवं सद्भाव की कामना की जाती है। इसी तरह हरछठ के दिन होलिया, मक्का, चना, बाजरा, ज्वार आदि की पूजा की जाती है।

उदास गंगा और खामोश हिमालय

कोरोना ने प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ता और कई सामाजिक आंदोलनों के सूत्रधार सुंदरलाल बहुगुणा को हमसे छीन लिया। हिमालय और गंगा के लिए चलाई गई मुहिम के जरिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले बहुगुणा पर्यावरण को एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए सदैव याद किए जाएंगे। वह एक ऐसे समय में हमसे विदा हुए, जब भोगवादी जीवन शैली व विकास के नाम पर प्रकृति के मर्दन से उत्पन्न महामारी और गंगा में शवों के तैरने जैसी अभूतपूर्व चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं।

तत्कालीन टिहरी रियासत के एक राजशाही समर्थक परिवार में पैदा हुए बहुगुणा की शिक्षा-दीक्षा उस समय के नामी संस्थानों में हुई थी। वह चाहते, तो उस वक्त टिहरी रियासत में किसी बड़े पद पर तैनात हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सुविधाजनक रास्ता चुनने के बजाय शोषित-पीड़ित जनता का साथ देने की राह चुनी। टिहरी रियासत के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह करने वाले श्रीदेव सुमन से प्रेरणा लेकर उन्होंने टिहरी को राजशाही से मुक्त करने के आंदोलन में खुद को समर्पित कर दिया। बहुगुणा ने कई बार राजशाही की हिंसा झेली, दमन झेला, लेकिन जनपरस्ती का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ देश में स्वतंत्रता आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ ही जब टिहरी में राजशाही के विरुद्ध आक्रोश बड़ने लगा, तब बहुगुणा इस मुहिम के अगुआ दस्ते में शामिल हो गए। राजशाही के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रजामंडल के वह अग्रणी नेताओं में शामिल रहे और देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए जुटी कांग्रेस के सचिव भी। लेकिन आजादी के बाद 1956 में बहुगुणा की जीवन-दिशा बदल गई, और इसमें उनकी पत्नी विमला बहुगुणा का बड़ा योगदान रहा। सर्वोदय कार्यकर्ता सरला बहन की शिष्या विमला बहुगुणा ने उनके सामने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद वह राजनीति नहीं, सिर्फ समाज सेवा करेंगे। इस शर्त ने बहुगुणा का जीवन-दर्शन तो बदला ही, उत्तराखंड में आजादी के बाद के शुरुआती जनांदोलनों का उन्हें अगुआ भी बना दिया।

बहुगुणा ने जैसे ही सक्रिय राजनीति छोड़कर सामाजिक आंदोलन शुरू किए, पूरे सामाजिक परिवेश में हलचल पैदा हो गई। उन्होंने उस दौर में समाज के हाशिये के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए छुआछूत विरोधी, दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने जैसे आंदोलन शुरू किए। इन आंदोलनों में भारी विरोध झेलने के बावजूद बहुगुणा अडिग रहे। इसके बाद उन्होंने नशे के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसके लिए भी उन्हें खूब विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह आंदोलन गड़वाल से कुमाऊं तक फैला और अंतत: सरकार को पूरे उत्तराखंड को नशामुक्त क्षेत्र घोषित करना पड़ा। हालांकि, 'सिस्टम' ने पहाड़ पर नशा के जारी रखने के दूसरे रास्ते निकाल लिए। धर्मग्रंथों में हिमालय की महिमा नई बात नहीं है। पर बहुगुणा ने देश-दुनिया की ऑक्सीजन, जल-भंडार व पर्यावरण-सुरक्षा में हिमालय के योगदान को महत्व दिलाने में अहम योगदान दिया। इस मुहिम में वह केवल आज के उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक पदयात्रा की, जिसने पूरे हिमालयी समाज को जोड़ने और उनकी पर्यावरणीय चिंताओं को एक-दूसरे से साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

टीकाकरण की कठिन राहः टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही टीके को लेकर लोगों की हिचक दूर करने का भी काम किया जाना चाहिए

संजय गुप्त

कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे-धीरे मंद पड़ रहा है, पर इसने देश के अंदर भय और पीड़ा की एक ऐसा मंजर छोड़ा है, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस महामारी से बचने का अगर कोई कारगर तरीका है तो वह सिर्फ तेजी से टीकाकरण है। भारत के वैज्ञानिकों और फार्मा क्षेत्र के उद्यमियों को इसके लिए दाद देनी होगी कि वे कम समय में टीका बनाने में सक्षम हो गए। जहां भारत बायोटेक ने अपने स्तर पर कोवैक्सीन टीका बनाया। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन में बने एस्ट्राजेनेका टीके का कोविशील्ड नाम से देश में उत्पादन सुनिश्चित किया। कोविड की पहली लहर दूसरी लहर के मुकाबले कहीं कम घातक साबित हुई थी, लेकिन टीके को लेकर जो संशय उपजा, वह समय रहते दूर नहीं हो सका। इस संशय का एक कारण टीके को लेकर की गई सस्ती राजनीति भी रही। कुछ विपक्षी दलों ने इसे भाजपा का टीका कहा तो किसी ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कुछ देशों में एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड लेने वालों में खून के थक्के जमने की समस्या के चलते भी टीकाकरण को लेकर कुछ लोगों में हिचक पैदा हुई। देर से ही सही, लोगों में टीके को लेकर विश्वास जगा, लेकिन अब टीकों की कमी आड़े आ रही है। हालांकि अपने देश में टीकाकरण 16 जनवरी से प्रारंभ हो गया था, लेकिन शुरू में उसकी गति बहुत धीमी रही। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगने थे, लेकिन अभी तक करीब 30 लाख स्वास्थ्यकर्मी ऐसे हैं, जिन्होंने टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है। कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने पहली खुराक भी नहीं ली। स्पष्ट है कि लोगों ने भी ढिलाई बरती। भारत सरकार ने भी प्रारंभ में जुलाई तक 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा। इसके लिए 60 करोड़ खुराक चाहिए होतीं। ऐसा लक्ष्य शायद इसलिए रखा गया, क्योंकि सरकार को यह आभास नहीं था कि महामारी की दूसरी लहर इतने भयंकर रूप में आएगी। संभवत: इसी कारण टीकों का आर्डर देने में देरी हुई। फिलहाल जरूरत भर टीके उपलब्ध नहीं हैं और इसी वजह से टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। पहले 32-35 लाख टीके प्रतिदिन लग रहे थे, अब उनकी संख्या घटकर 17-18 लाख रह गई है। टीकों की कमी दूर करने के लिए जहां केंद्र सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में टीका बनाने की अनुमति दी है, वहीं राज्यों ने अपने स्तर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार से टीका खरीदने की पहल की है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं कि वे कब तक टीके हासिल कर पाएंगे। जिन विदेशी कंपनियों के टीकों का भारत में उत्पादन होना तय हुआ है, उनमें केवल रूसी टीका स्पुतनिक का ही उत्पादन शुरू होता हुआ दिख रहा है।

हालांकि राज्य सरकारें इससे परिचित हैं कि टीकों की उपलब्धता आनन-फानन में सुनिश्चित नहीं की जा सकती, फिर भी वे और खासकर दिल्ली और बंगाल की सरकारें सस्ती राजनीति करने में लगी हुई हैं। उन्हें इससे अवगत होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने जुलाई तक 51 करोड़ टीके खरीदने और दिसंबर तक टीकों की 216 करोड़ खुराक का इंतजाम करने को कहा है। उम्मीद है कि जुलाई के बाद टीकों की तंगी खत्म हो जाएगी, लेकिन टीकों की उपलब्धता बड़ाने के साथ टीकाकरण में तेजी लाने की भी जरूरत होगी। कम से कम 50-60 करोड़ लोगों का टीकाकरण होने के बाद ही महामारी की तीसरी लहर का सामना सफलता से किया जा सकता है। अभी तक 19 करोड़ लोगों को ही टीका लग सका है। साफ है कि अभी लंबा सफर तय किया जाना शेष है। चूंकि ऐसी स्थिति बन सकती है कि लोगों को हर साल टीके लगवाने पड़ें, इसलिए सरकार को लंबे समय के लिए पर्याप्त टीके की व्यवस्था करने के लिए कुछ ठोस उपाय करने होंगे।

जिन देशों में कोविड की तीसरी लहर चल रही है, वे टीकाकरण के कारण ही हाहाकार से बचे हुए हैं। दूसरी लहर के वक्त उनकी भी स्थिति भारत की तरह दयनीय थी। साफ है कि यदि भारत में तेज गति से टीकाकरण हो रहा होता तो भी शायद दूसरी लहर के वक्त पर्याप्त संख्या में लोगों को टीके नहीं लग पाते। जो भी हो, अब जब महामारी की तीसरी लहर आनी है, तब टीकाकरण को तेज करने की कोशिश की जानी चाहिए। तीसरी लहर कब आएगी, इसके बारे में अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं। जरूरी यह है कि उसका सामना करने की पूरी तैयारी की जाए।

होटल बंद और शादी समारोह न होने से किसानों को नुकसान

ग्वालियर के कोल्ड स्टोरेज फुल मांग कम, गिरे आलू के भाव

संवाददाता, ग्वालियर

कोरोना कर्फ्यू से होटल और शादियां बंद हैं। मंदिरों में पूजा पाठ भी प्रशासन ने रोक रखा है। इसका सबसे ज्यादा असर आलू और फूल उत्पादक किसानों पर हुआ है। आलू की मांग कम होने से इसके दाम गिर गए हैं। कोल्ड स्टोरेज में भी इन्हें रखने के लिए जगह नहीं बची है।

कुछ किसानों ने घर में स्टोर कर लिया है पर रखे-रखे मौसम गर्म होने से आलू खराब होने लगे हैं। जबकि फूलों की मांग खत्म होने से अब किसानों से इन्हें खेतों से तोड़ना ही बंद कर दिया है। इस कारण फूल खेतों में ही सूखने लगे हैं।

दस रुपए किलो आलू

भगवानपुरा (सिरसौद) के किसान कदम सिंह ने कहा कि आलू के भाव बहुत गिर गए हैं। मुश्किल से 10 रुपए किलो बिक रहा है। इसके लिए भी गोहद की मंडी तक जाना पड़ रहा है। 300 बोरी आलू कोल्ड स्टोर में रख दी है। कुछ घर में रखा है, उसे कूलर की हवा देनी पड़ रही है। अप्रैल की शुरुआत में 15 से 20 रुपए किलो तक भाव मिल रहा था। रिछेरा के नरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गांव में 34 कोरोना मरीज मिलने से कंटेनमेंट बन चुका है। घर में जो आलू रखा है वह खराब हो रहा है। कोल्ड स्टोर में अब जगह नहीं बची है।

नींबू सबसे मंहगा

बाजार में इन दिनों हरी सब्जी के दाम नियंत्रण में है। थोक मंडियों में हरी सब्जी 10 से 15 रुपए किलो बिक रही है, जबकि यही ठेलों पर 20 से 30 रुपए किलो में। टमाटर इन दिनों काफी सस्ता है। थोक मंडी में 3-4 रुपए किलो में टमाटर मिल रहे हैं, जबकि ठेलों पर 10 रुपए किलो। नींबू थोक मंडी में 15 से 40 रुपए में क्वालिटी के आधार पर बिक रहा है। यही हाथ ठेलों पर 40 से 80 रुपए तक।

15 रुपए किलो में भी नहीं बिक रहा गुलाब

फूल उत्पादक किसान नत्थू सिंह कुशवाह ने एक चर्चा के दौरान कहा कि पांच बीघा में गुलाब लगाते हैं। मंडी में 15 रुपए किलो के भी भाव नहीं मिल रहे हैं। इससे ज्यादा खर्च तो तुड़ाई में होता है। चूंकि मंदिर बंद हैं इसलिए बाजार में डिमांड नहीं है। आधे से ज्यादा फूल तो अब खेत में ही खराब होने लगे हैं। ग्वालियर में फूल का तेल निकालने की व्यवस्था नहीं है। दाल बाजार में गुलकंद बनाने वाले लोगों से संपर्क किया था, उन्होंने भी गुलाब खरीदने से इंकार कर दिया है। अब तो घाटा होना तय है।

स्वस्थ-निरोग पक्षी ही सफल मुर्गी पालन का आधार

मुर्गियों का अधिक उत्पादन प्राप्त करने गर्मी से बचाएं

संवाददाता, टीकमगढ़

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के वैज्ञानिकों ने सम-समयाकी के तहत बताया कि स्वस्थ-निरोग पक्षी ही सफल मुर्गी पालन का आधार है। पशुपालन वैज्ञानिक डॉ. एसके खरे और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बीएस किरार ने बताया कि गर्मियों में अधिकतर मुर्गियां परेशान हो जाती हैं, क्योंकि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसी ही न सिर्फ अंडा उत्पादन में कमी बल्कि मुर्गियों में मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, कारण मुर्गी गर्मी में कम खाना खाती है। आहार कम लेने से अंडा उत्पादन कम होने के साथ-साथ अंडों का आकार भी छोटा हो जाता है। यही नहीं अंडों के ऊपर का कवच कमजोर व पतला हो जाता है, जिससे मुर्गी पालक को काफी हानि होती है। जब मुर्गी शाला का बाहरी तापमान 39 डिग्री सेटीग्रेड से अधिक होने लगता है तब मुर्गियां बहुत परेशान हो जाती हैं। इस स्थिति को हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें मुर्गियां चोंच खलकर हॉफती हैं कमजोर हो जाती हैं, लड़खड़ाने लगती हैं। इसके बाद लकवा होने से मर जाती हैं। मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाना चाहिए।

मुर्गियों को बचाने के अहम उपाय:

आहार: गर्मी के मौसम में आहार खपत में कमी आ जाती है। अत: आहार में प्रोटीन, विटामिन व मिनरल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए ताकि कम खाने पर भी आवश्यक पोषक तत्व मुर्गी को प्राप्त हो सकें। गर्मी में अंडों का छिलका पतला होने से बचाने के लिए आहार में कैल्सियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इसके लिए दाने में ऑस्टो कैल्सियम लिक्विड पानी में दिया जा सकता है।

पानी: गर्मी में मुर्गियों में पानी की खपत दुगुनी हो जाती है। इसके लिए मुर्गी घर में हर समय स्वच्छ और ठंडा जल उपलब्ध रहना जरूरी है। पानी के बर्तन प्लास्टिक व जस्ते के होने की बजाय मिट्टी के होने चाहिए, क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है।

बिछावन: गर्मी में मुर्गी के बिछावन (लीटर) की मोटाई 2 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि लीटर पुराना हो गया हो तो उसे हटाकर नया लीटर काम में लेना चाहिए।

रोशनी: मुर्गियां ठंडे समय में दाना खाना पसंद करती हैं। अत: दिन की रोशनी के अलावा बिजली की रोशनी सुबह के ठंडे मौसम में ज्यादा देनी चाहिए, ताकि मुर्गियां आहार का पूर्ण उपयोग कर सकें। सामान्यत: मुर्गियां 60 एफ से 80 एफडिग्री के बीच का तापमान पसंद करती हैं, क्योंकि इस तापक्रम पर मुर्गियों की खुराक और अंडा उत्पादन की दर अधिकतम होती है। इससे अधिक तापमान होने से मुर्गियों का खाना और अंडा उत्पादन कम होता है।

ऐसे बढ़ेगा अंडा उत्पादन: तापमान अधिक होने पर इन उपायों से उसे कम करके अधिक अंडा उत्पादन लिया जा सकता है। इसमें कुक्कुट शाला की छत की बाहरी परत पर सफेद पेंट कर देना चाहिए, जिससे सूर्य की किरणें छत से टकराकर वापस लौट जाएं। छत पर, स्बेस्टास की शीट भी लगाई जा सकती है। खिड़कियों से उसे 3-5 फीट की दूरी पर टाट के पर्दे लगाकर और उनमें पानी का छिड़काव करके मुर्गीघर को ठंडा किया जा सकता है। फोगर्स न हो तो इसके द्वारा भी कुक्कुट शाला का तापमान कम कर सकते हैं।

कृषि विश्व विद्यालय और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच हुआ समझौता

कृषि-इंजीनियरिंग कॉलेज करेंगे शोध

संवाददाता, जबलपुर

कृषि यंत्र और खेती की आधुनिक तकनीक के नए रास्तों को खोला जाएगा

मौजूदा समय को देखते हुए अनुसंधान और उसमें किए जाने वाले कार्यों में परिवर्तन करना अब जरूरी हो गया है। खासतौर पर ऐसे अनुसंधान जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़े हैं। शोध का दायरा बढ़ाते हुए इंजीनियरिंग के अनुभवी कृषि के अनुभवियों के साथ मिलकर शोध को नई दिशा देंगे।

दरअसल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच शोध कार्य करने के लिए समझौता हुआ है, जिसने कृषि और इंजीनियरिंग में अनुसंधान के नए रास्ते खोल दिए हैं। कृषि और इंजीनियरिंग दोनों मिलकर भविष्य की चुनौतियों से लड़ने में कारगर शिद्ध होंगे। हाल ही में दोनों कॉलेज के बीच एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू के तहत कृषि से जुड़े क्षेत्रों में इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करेंगे। कृषि यंत्र और खेती की आधुनिक तकनीक के नए रास्तों को खोला जाएगा। कृषि विवि और जीईसी के बीच हुए एमओयू हस्तांतरण को लेकर जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि के कुलपति प्रो. प्रदीप बिसेन ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को लड़ने में तकनीकी मददगार है। ऐसे में कृषि के क्षेत्र में भी कई चुनौतियां हैं, जिसमें कम लागत, अधिक उत्पादन और छात्रों को कृषि से जोड़ना शामिल है। कृषि क्षेत्रों में नए अनुसंधान की जरूरत महसूस की जाने लगी है। ऐसे में विवि और इंजीनियर कॉलेज के बीच किया गया यह एमओयू मददगार साबित होगा। विश्वविद्यालय के डीन फैकल्टी प्रो. धीरेंद्र खरे, डायरेक्टर रिसर्च प्रो पीके मिश्रा ने कहा कि कुशल इंजीनियर और माटी के जानकारों की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। प्रो. अभिषेक शुक्ला ने कहा कि यह एमओयू दोनों संस्थाओं के लिए नीव का पत्थर साबित होगा। हम भविष्य की चुनौतियों को इस एमओयू की मदद से निपट सकते हैं और जल्द ही हम खेती व इंजीनियरिंग को जोड़कर एक नई इबारत लिखेंगे। इससे किसानों को सबसे अधिक फायदा होगा।

विश्व मधुमक्खी दिवस पर बेबीनार

मधुमक्खियों की कमी से प्रभावित हो रही खेती और पर्यावरण

सागर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निर्देशानुसार कृषि विज्ञान केंद्र सागर, बिजौरा, देवरी द्वारा 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर किसानों और आदान विक्रताओं के लिए मधुमक्खी पालन व प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जहां केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आशीष त्रिपाठी ने कहा कि आधुनिक कृषि में रासायनिक कीटनाशियों का प्रयोग ज्यादा होता है। इससे धीरे-धीरे मधुमक्खियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जिसका पर्यावरण व कृषि दोनों पर दुष्प्रभाव पढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के फसलों में मधुमक्खियों द्वारा पराग की प्रक्रिया से 2 से 31 प्रतिशत तक उपज में वृद्धि होती है। मधुमक्खियों से शहद के साथ-साथ फसलों में पराग एवं अन्य सह उत्पाद जैसे, मोम, वेनम, रॉयल जेली, परागकण, प्रोपोलिस आदि भी प्राप्त होता है। डॉ. त्रिाठी ने मधुमक्खियों का जीवनचक्र, मधुमक्खी के प्रबंधन और रख रखाव पर भी प्रकाश डाला। साथ ही मधुमक्खीपालन से प्रतिवर्ष कुल लाभ का भी ब्यौरा समझाया। कार्यक्रम में केन्द्र के मयंक मेहरा, सुखलाल वास्केल सहित 41 किसान और आदान विक्रताओं ने भाग लिया।

लेबर की कमी तो रोपा की बजाय सीधे धान की बोवनी की तरफ बढ़ा रुझान

सीधे बोवनी में 15 हजार और रोपा लगावाने में प्रति एकड़ 30 हजार का खर्च

बदलेगा धान की बोवनी का पैटर्न

बीते साल 1.71 हजार हेक्टेयर में बोयी थी धान, इस बार 2.30 लाख हेक्टेयर लक्ष्य

संवाददाता, रायसेन

जिले में किसानों ने खरीफकी बोवनी के लिए खेत तैयार करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि, मानसून आने में अभी एक महीना बाकी हैं। इतना ही नहीं डीजल के रेट बढ़ने के साथ ही कोरोना कर्फ्यू के चलते दूसरे प्रदेशों से आने वाली लेबर के आने पर भी संशय बरकरार है। इन सब कारणों से किसान इस बार धान की फसल में लगने वाली लागत कम करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए धान का रोपा लगाने की जगह सीधी बोवनी भी करने की तैयारी कर रहे हैं। सीधी बोवनी से धान की लागत में 40 से 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है। जहां एक रोपे लगाकर धान की फसल लेने में प्रति एकड़ 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है, तो वहीं धान की सीधी बोवनी करने में 15 हजार रुपए एकड़ में ही काम हो जाता है। सबदलपुर गांव के उन्नत किसान मिट्ठूलाल मीणा का कहना है कि इस बार डीजल बहुत महंगा हो गया है। वहीं कोरोना कर्फ्यू के कारण दूसरे प्रदेशों से आने वाली लेबर भी नहीं आ रहे हैं। इस तरह से रोपा वाली धान लगा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए तय किया है 80 एकड़ रकबे में से आधी जमीन में सोयाबीन और गेहूं की तरह धान की सीधी बोवनी करेंगे। वहीं आधी ही जमीन में धार का रोपा लगाएंगे। इसी तरह दूसरे किसान भी धान की सीधी बोवनी करने की बात कह रहे हैं।

सीधी बोवनी में कम लागत

किसानों और खेती के जानकारों के मुताबिक धान का रोपा लगाने के लिए सबसे पहले खेतों को समतल कर उनमें गड़े बनाए जाते हैं। गड़े बनाने में प्रति एकड़ 3 हजार रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है। इसके बाद बारिश होने पर खेतों को ट्रैक्टर से मचाना पड़ता है। इसमें भी दो हजार रुपए प्रति एकड़ किसानों को खर्च करना होता है। इसके बाद जब धान की फसल कट जाती है तो खेतों में बने गड़े मिटाकर खेत समतल करने में भी 2 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से राशि खर्च करना होती है। इसके अलावा खेत में धान का रोपा लगाने पर 3 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से लेबर पर राशि खर्च करना होती है। इस तरह से 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की राशि अतिरिक्त खर्च कराना होती है, जबकि धान की सीधी बोवनी में यह खर्च बच जाता है।

कृषि मंडी में मिलता है अच्छा रेट

शहर की कृषि उपज मंडी धान के लिए प्रदेश में जानी जाती है। छोटी मंडी होने के बावजूद पांच जिलों के किसान यहां धान बेचने के लिए आते हैं। मंडी में चावल निर्माता बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने एजेंट के माध्यम से धान की खरीदी करते हैं। इसलिए यहां किसानों को धान के रेट भी अच्छा मिलता है। इससे सोयाबीन की तुलना में धान फायदे की फसल बनी हुई है।

सोयाबीन से मोह भंग

जिले में पहले सोयाबीन ही खरीफकी मुख्य फसल हुआ करती थी, लेकिन बीते सालों से किसानों को हो रही घाटे के चलते वे धान अधिक लगाने लगे हैं। इससे सोयाबीन के रकबे में कमी आई है। वर्ष 2019में 1 लाख 98 हजार हेक्टेयर में धान लगाई थी, जबकि सोयाबीन की बोवनी महज 91 हजार हेक्टेयर में की गई थी। वर्ष 2021 में बोवनी के समय बारिश कम होने से सोयाबीन का रकबा बढ़कर 99 हजार हेक्टेयर रहा, जबकि धान की बोवनी भी उम्मीद भी उम्मीद से कम 1 लाख 71 हजार हेक्टेयर में की गई। अब वर्ष 2021 के लिए 2 लाख 30 हजार हेक्टेयर में धान की फसल का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा तय किया गया है। बीते साल सोयाबीन की फसल में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए उनका रुझान धान की बोवनी की तरफ अधिक रहेगा।

इनका कहना है

धान की सीधी बोवनी में लागत कम आती है। इसके लिए अलग से खेत तैयार नहीं करने पड़ते। वहीं पौधरोपण में लगने वाला लेबर खर्च भी बचता है। साथ ही पानी की जरूरत भी अधिक नहीं होती है। इस तरह से धान की सीधी बोवनी, रोपा वाले पैटर्न से कम खर्च वाली है। हालांकि, बीज 20 से 25 किलो प्रति एकड़ लगता है, जबकि रोपा वाले पैटर्न में 5 से 10 किलो, लेकिन दूसरे खर्चे बचने से सीधी बोवनी से लागत कम की जा सकती है। साथ ही उत्पादन में भी ज्यादा अंतर नहीं आता है। प्रति एकड़ 4 से 5 क्विंटल की कमी आती है।

डॉ. स्वप्निल दुबे, कृषि वैज्ञानिक,
नकतरा, कृषि विज्ञान केंद्र

प्री मानसून गतिविधियों के साथ खरीफ की तैयारी में जुटे किसान

उज्जैन। बादलों की आवाजाही और बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वे कोरोना संक्रमण के बीच खरीफ फसल की तैयारियों में जुट गए हैं। खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें बंद होने से अब तक वे गांवों में ही थे, लेकिन अब दुकानें खुलने के बाद उन्हें शहर आना पड़ रहा है। कृषि विभाग के अफसरों का दावा है कि खाद, बीज की कोई कमी नहीं है। किसानों का कहना है कि कमी नहीं है तो उसे शहर में दुकानों पर बेचने की जगह गांव की सेवा सहकारी समितियों में भेजा जाए। इससे किसानों को लंबा सफर और जान जोखिम में डालकर शहर नहीं आना पड़ेगा। कृषि उपज मंडी में निजी और सरकारी दोनों खाद वितरण केंद्र पर किसान बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए कतार में लगे दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि गांवों की सेवा सहकारी समितियों में खाद तो है लेकिन बीज और कीटनाशक नहीं है। ऐसे में वे एक सामान वहां से लें और दो के लिए शहर आएं। इससे अच्छा है वे खाद-बीज और कीटनाशक सभी शहर से ले लें। ऐसे में उन्हें न चाहकर भी शहर आना पड़ रहा है।

सलाह : 10 मीटर के अंतराल में सब सॉइलर चलाएं: भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर ने किसानों को सलाह दी है। डीडीए सीएल केवड़ा ने बताया उत्पादन में स्थिरता के लिए दो से तीन वर्ष में एक बार खेत की गहरी जुताई करें। बक्खर, कल्टीवेटर और पाटा चलाकर खेत को तैयार करें।

किस्म : जिन किसानों के पास खुद का बीज है वे उसका अंकुरण-परीक्षण कर लें। कम से कम 70 प्रतिशत अंकुरण क्षमता वाला बीज ही बोएं। जिले में अनुशंसित किस्में जेएस 95-60, जेएस 93-05 और नवीन किस्में जेएस 20-34, जेएस 20-29 और आरवीएस 2001-04 प्रमुख हैं।

गोबर खाद डालें किसान: किसान खेत की अंतिम बखरनी के पहले गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर या मुर्गी की खाद 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर खेत में फैला दें। सोयाबीन की बोवनी के लिए मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का समय उपयुक्त है।

पाकिस्तान तक जाता था सुहागपुर का बंगला पान, किसानों को बांस, बल्ली, सागौन नहीं मिल रहे, सुहागपुर में बढ़ रहा बरेजों का तापमान

बंगला पान की खेती पर मंडराते संकट के बादल

संवाददाता, सोहागपुर

लागत की अधिकता और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के चलते शहर में होने वाली बंगला पान की खेती का व्यवसाय धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। दो-तीन दशक पहले शहर में जहां सैकड़ों की संख्या में किसान पान की खेती के व्यवसाय से जुड़े थे, वहीं अब इनकी संख्या दजज़न भर के आसपास सिमट कर रह गई है। लागत की अधिकता और प्राकृतिक संसाधनों की कमी ने क्षेत्र के किसानों को दूसरा व्यवसाय करन के लिए मजबूर कर दिया है।

अपने लाजवाब स्वाद एवं कड़कपन के चलते शहर के नाम से पहचान बनाने वाले सोहागपुरी बंगला पान की मांग आज भी बनी हुई है। प्रदेश ही नहीं प्रदेश के बाहर एवं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बंगला पान को खूब पसंद किया जाता है।

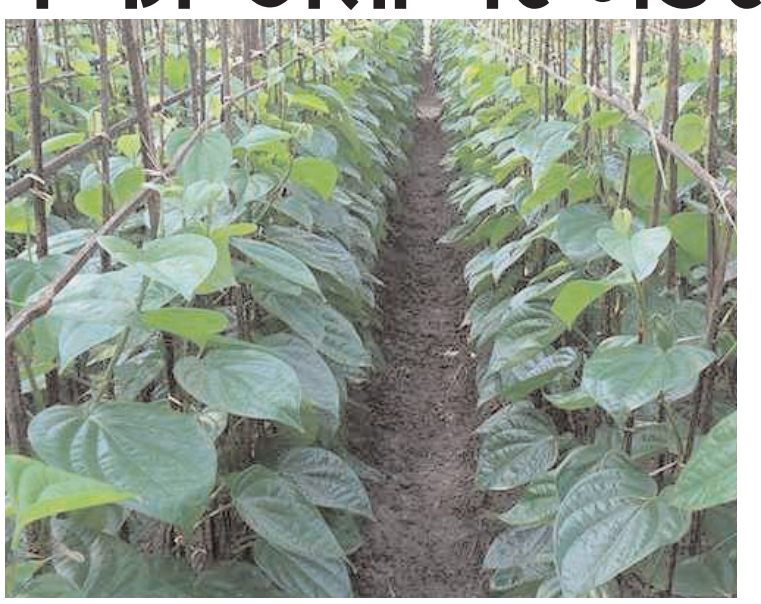

घास, बांस, बल्ली की कमी

पान की खेती से जुड़े किसान महेश चौरसिया और सुरेश चौरसिया बताते हैं कि बंगला पान की खेती के लिए पहले पान बरेजा बनाया जाता है। इसके अंदर पान की खेती की जाती है, जो की पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। पान बरेजा बनाने के लिए किसानों को घास, बांस, बल्ली, सागौन, के पत्ते बक्कल आदि की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आज से बीस तीस वर्ष पूर्व आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन वन विभाग द्वारा जंगल से अब इन चीजों को लाने नहीं दिया जाता है। इसके चलते बरेजा बनाने में किसानों को आधुनिक चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं जिसमें प्लास्टिक का नेट प्लास्टिक की रस्सी पाइप आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं।

किसानों को हो रहा नुकसान

पान बरेजा के अंदर पहले जैसा तापमान नहीं बन पाता है और ना ही उसे इतनी मजबूती मिल पा रही है। जिसके चलते थोड़े से आंधी तूफान में पान बरेजा गिरकर जमींदोज हो रहे हैं। जिससे व्यवसाय से जुड़े किसानों की आर्थिक नुकसान होता है और उनकी स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। बरेजा बनाने में प्राकृतिक संसाधन नहीं मिल पाने के कारण पान के पौधे ठीक से नहीं पनप पा रहे है। जिसकी वजह से बंगला पान धीरे धीरे कम होते जा रही है। आधुनिक पान की खेती में लागत अधिक एवं मुनाफा कम रह गया है। जिससे परंपरागत व्यवसाय से जुड़े किसानों पर अधिक भार पड़ रहा है। जिसके चलते किसान अपनी परंपरागत खेती से दूर होते जा रहे हैं।

कोरोना से मौत पर पीड़ित परिवार को सरकार देगी 'अनुग्रह'

- सीएम शिवराज बोले, प्रदेश में एक जून से जनता कर्फ्यू खोलेंगे
- अब तक सात हजार से अधिक मौत, हर परिवार को मिलेंगे एक लाख रुपए
- प्रदेश सरकार 73 करोड़ रुपए खर्च कर देगी पीड़ित परिवारों को राहत
- राशि पर पहला हक मृतक की पत्नी या पति का होगा
- योजना की अवधि 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक रहेगी
- दावा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

कोरोना संकट में जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उन्हें तात्कालिक राहत देने के लिए प्रदेश सरकार कई करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जिस परिवार में कोरोना से मौत हुई है, उस परिवार को राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रदेश में अभी तक मरने वालों की संख्या 7394 है। इस हिसाब से अभी तक सरकार पर 73 करोड़ से अधिक का आर्थिक भार आएगा। कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। ऐसे में अनुग्रह राशि का आंकड़ा भी बढ़ेगा। हालांकि भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिनके घर संकट आया है, हम उन्हें केवल शाब्दिक सहानुभूति नहीं दे सकते। अनुग्रह राशि देने के पीछे उद्देश्य यह है कि इससे परिवार को कुछ सहारा हो जाए।

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश: कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा कर्मी के पति अथवा पत्नी को दिया जाएगा। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। योजना के मुताबिक मृत कर्मचारी की कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है। राशि पर पहला हक मृतक की पत्नी अथवा पति का होगा। जिस दिन मौत हुई, उस दिन शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है। वर्तमान में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आदेश के मुताबिक परिवार में एक से अधिक सरकारी सेवक के पात्र होने पर प्रत्येक सदस्य के निधन पर अलग-अलग राशि दी जाएगी। कोरोना से मृत सरकारी सेवक को पूर्णकालिक होना चाहिए। अंशकालिक सेवक को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

पात्र दावेदारों में बांटी जाएगी राशि: सरकारी कर्मचारी इस अवधि के दौरान कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन उसकी मृत्यु योजना अवधि समाप्त होने के बाद संक्रमित होने के 60 दिन के भीतर हो जाती है, तो भी पात्र दावेदार को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी।

निगम मंडलों के लिए नियम: निगम - मंडल - राज्य शासन के अधीन निगम और मंडलों और विश्वविद्यालय नियमित, स्थाई, दैनिक वेतन भोगी, संविदा और आउट सोर्स कर्मचारी के मामले में उनके शासी निकाय के अनुमोदन से योजना लागू कर सकते हैं। राशि का भुगतान भी स्वयं की निधि से होगा।

नगरीय निकाय व पंचायत संस्थाएं - यहां कार्यरत नियमित, स्थाई, दैवेभो, संविदा और आउट सोर्स कर्मचारी के मामले में अंतिम स्वीकृति जिले के कलेक्टर देंगे।

ब्लैक फंगस महामारी घोषित

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस माह के अंत तक प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी शून्य करना है, जिससे अगले माह से प्रदेश में जन-जीवन सामान्य कर सकें तथा काम धंधे चालू हो सकें। प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एग्रेसिव टेस्टिंग करें। कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग करें तथा माइक्रो कंटनमेंट जोन बनाएं। कोरोना के एक-एक मरीज को ढूंढ निकालें, उसका इलाज करें तथा कोरोना संक्रमण को पूरी तरत समाप्त करें। प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाता है। इस बीमारी के उपचार की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें इंजेक्शन एम्फोटैरिसिन बी मिल जाए, यह तय किया जाए।

जून में अनलॉक होगा एमपी

सीएम ने प्रदेशभर के जनप्रतिनिधियों से वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए कहा कि 1 जून से मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू को खोलना है, लेकिन खोलना इस तरह है कि फिर से इसका संक्रमण फैलने न पाए। कोरोना के खिलाफ हम एक लंबा युद्ध लड़ रहे हैं और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में पाजिटिविटी रेट घटकर 4 प्रतिशत के करीब रह गया है। 5 प्रतिशत तक संक्रमण की दर होने का अर्थ है कि यह नियंत्रण में है। कुछ बड़े जिलों में अभी भी काफी केसेस हैं। 31 मई तक हमें कोरोना संक्रमण को काबू में करना है।

लॉकडाउन में बढ़ गया तितली और चमगादड़ का कुनबा

कोरोना में जैव विविधता में दिखे सकारात्मक प्रभाव

भोपाल। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन का प्रकृति और जैव विविधता पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। कोरोना काल को एक साल से अधिक हो गया है। इस दौरान ज्यादातर समय नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन में बीता है। इस दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगी है। इंसानों के घर में सीमित होने से जैव विविधता को पनपने का अवसर मिला है। भोपाल शहर में इस साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आए। वायु प्रदूषण घटने से तितलियों की संख्या भी बढ़ी और चमगादड़ भी अधिक नजर आ रहे हैं। पक्षियों पर नजर रखने वाले समूह भोपाल बर्ड के मोहम्मद खालिक ने बताया कि गत वर्ष विश्व के अधिकतर देशों में लॉकडाउन था। इस वजह से सुदूर देशों से भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों को आसानी हुई। आकाश में प्रदूषण न होने होने से रास्ते में उन्हें परेशानी नहीं हुई। भोज वेटलैंड में आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि देखी गई थी। अक्टूबर से फरवरी- 2021 के बीच 30 हजार से ज्यादा प्रजातियां गणना में मिली थीं, जिनमें से ज्यादातर बतख थे, जो साइबेरिया और यूरोप से आए थे। जल प्रदूषण कम होने से इस दौरान उन्हें तालाब किनारे भोजन भी प्रचुर मात्रा में मिला। इसी प्रकार वाहनों और फैक्ट्रियों के बंद होने से वायु प्रदूषण कम हुआ, जिसकी वजह से तितलियों की संख्या बढ़ी है। तितलियां विशेष प्रकार की छोटी झाड़ियों में पत्तों के नीचे अंडे देती हैं। वायु प्रदूषण से उनके अंडे नष्ट हो जाते थे, जो कि इस बार नहीं हुए। इसी प्रकार लॉकडाउन में पक्षियों का जीवन चक्र भी सुलभ हुआ है।

इनका कहना है

कोरोना काल के बाद जैव विविधता में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। वन अपराध बंद हो गए। पर्यावरण प्रदूषण और प्रकृति में इंसानी दखल कम होने से सभी तरह के जीव-जंतु उन्मुक्त विचरण कर रहे हैं। उनकी प्रजजन क्षमता भी बढ़ गई है। सभी प्रजाति की तितलियां, मधुमख्खी के छत्ते और रंग-बिरंगे पक्षी हर तरफ दिख रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं दिखते थे। **-डॉ. सुदेश वाघमारे,** वाइल्ड लाइफएक्सपर्ट

कोरोना संक्रमण के बाद शहरीकरण, औद्योगिकीरण और वृक्षों की कटाई धीमी होने से प्राणियों के रहवास में मनुष्यों का हस्तक्षेप कम हुआ और उनकी स्वच्छंदता बढ़ी है। उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है। रात में शांति से शहर में अधिक चमगागड़ दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान वन विहार में भी पशु-पक्षी दूर-दूर तक विचरण करते देखे जा रहे हैं। **-डॉ. रेखा श्रीवास्तव,** प्राध्यापक, एमबीएम

'बाहुबली-आरोही-चाइना' तरबूज की खेती से किसान आत्मनिर्भर

अनूपपुर के आदिवासी लाकडाउन में कमा रहे 17 हजार रुपए प्रति दिन, तरबूज-खरबूजे से लोगों को मिल रहा काम, काश्तकार हो गए लखपति

संवाददाता, अनूपपुर

तरबूज की खेती कर कोतमा तहसील क्षेत्र के ग्राम सारंगढ़ निवासी कौशल प्रजापति प्रतिदिन 17 हजार रुपए कमा रहे हैं। कोरोना के इस संकटकाल में भी उनकी रोजी-रोटी अच्छी चल रही है। महज तीन साल पहले तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सिर्फ धान की खेती पर आजीविका चल रही थी।

उसी दौरान उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले ने उन्हें और कई काश्तकारों को इकट्ठा कर तरबूज और खरबूजे की खेती करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें तरबूज-खरबूजे की खेती करने के गुर सिखाए। कौशल प्रसाद कहते हैं कि तरबूज और खरबूजे की खेती ने अब सारी टेंशन खत्म कर दी। पहले गृहस्थी चलाने और बच्चों की परवरिश को लेकर बहुत चिंता रहती थी। लॉकडाउन में भी इनकी फसलें भरपूर मुनाफा दे रही हैं। जिले में इस साल तरबूज, खरबूजे की अच्छी पैदावार हुई है और कई गांवों के किसान इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।

बढ़ गया खेती का रकबा

अनूपपुर जिले में करीब 235 हेक्टेयर में तरबूज और कुल 205 हेक्टेयर में खरबूजे की खेती हो रही है। इसमें से उद्यानिकी विभाग की प्रेरणा एवं मदद से किसान लगभग 56 हेक्टेयर में तरबूज और 21 हेक्टेयर में खरबूजे की खेती कर रहे हैं, जिनमें आधे आदिवासी हैं। तरबूज-खरबूजे के उत्पादन से कई हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है और तमाम काश्तकार लखपति बन गए हैं। लॉकडाउन में भी इनकी आजीविका प्रभावित नहीं हो पाई।

छत्तीसगढ़ में बढ़ी मांग

ग्राम सारंगगढ़ के काश्तकार कौशल प्रसाद प्रजापति ने, जो अपने खेतों में तरबूज एवं खरबूजे की खेती कर 17000 से 18000 प्रतिदिन कमा रहे हैं। किसानों में चाइना के नाम से मशहूर इस तरबूज की प्रसिद्धि का आलम यह है कि छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ एवं केल्हारी तक के व्यवसाई यहां आकर इस तरबूज की मांग कर रहे हैं। कौशल ने इस साल अपने यहां बाहुबली, आरोही, शक्ति चाइना तरबूज की तीन प्रजातियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया है। कोयले की खानों के लिए दुनियाभर में मशहूर अनूपपुर जिले के ग्राम सारंगगढ़ के रहने वाले कौशल प्रसाद ने धान उगाने से खेती का सफर शुरू किया था। मगर अधिक मुनाफा ना होने की वजह से उद्यानिकी विभाग की सलाह और तकनीकी मार्ग दर्शन लेकर अनुदान बतौर ड्रिप, मलचिंग, वीडर, कैरेट जैसे संसाधनों की बदौलत तरबूज, खरबूजे एवं खीरे की खेती शुरू कर दी। कौशल को सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं थी कि सरकारी संसाधनों से आरंभ तरबूज एवं खरबूजे का उत्पादन उन्हें लखपति बना देगा।

एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया

कौशल ने अपने बलबूते ना सिर्फ तरबूज एवं खरबूजे उत्पादन का व्यवसाय स्थापित कर लिया, बल्कि इससे हुई कमाई से मकान बनवा लिया, एक ट्रैक्टर खरीद लिया और एक मोटरसाइकिल भी खरीद ली। कोरोना काल के पूर्व राज्य सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों के जरिए आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को अनुदान बतौर ड्रिप, मलचिंग शीट, वीडर, पावर ट्रिलर जैसे उपकरण दिए गए थे, जिससे शुरू की गई उद्यानिकी फसलों की खेती के अच्छे नतीजे अब सामने आने लगे हैं। लॉकडाउन के चलते जब रोजगार की लगभग सभी गतिविधियां बंद हैं। वहीं काश्तकार सरकारी संसाधनों के माध्यम से तरबूज एवं खरबूजे का उत्पादन कर स्वयं के परिवार के साथ अन्य लोगों की भी आजीविका चलाने में सफल हो रहे हैं।

मऊगंज में पहला प्रयोग हुआ सफल

विंध्य में भी अब होने लगी शहतूत की पैदावार

अभी सिर्फ घर में कर रहे उपयोग

संवाददाता, रीवा

मध्यप्रदेश के विंध्य में भी अब शहतूत की पैदावार होने लगी है। अभी तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, आंध्रा प्रदेश और तामिलनाडू मुख्य शहतूत उत्पादक राज्य माने जाते थे। लेकिन अब इसमें मप्र भी शामिल होता नजर आ रहा है। दरअसल, रीवा जिले की तहसील मऊगंज की ग्राम पंचायत मऊबगदरा के प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्रा ने अपने घर पर ही प्रयोग के तौर पर शहतूत के कुछ पौधे लगाए हैं। अब उन पौधों ने फल देना शुरू कर दिया है। हालांकि वो अभी इन फलों को बाजार में बेच नहीं रहे हैं, बल्कि घर के ही इस्तेमाल में ला रहे हैं। गौरतलब है कि शहतूत को वानस्पतिक रूप में मोरस अल्बा के नाम से जाना जाता है। शहतूत के पत्तों का प्राथमिक उपयोग रेशम के कीट के तौर पर की जाती है। शहतूत से काफी औषधीय जैसे कि रक्त टॉनिक, चक्कर आना, कब्ज, टिटनेस के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके फल का जूस भी बनाया जाता है। जो कि कोरिया, जापान और चीन में काफी प्रसिद्ध है। यह एक सदाबहार वृक्ष होता है। इसकी औसतन ऊंचाई 40-60 फीट तक होती है। इसके फूलों के साथ-साथ ही जामुनी-काले रंग के फल होते हैं।

जमीन की तैयारी

शहतूत की खेती के लिए, अच्छी तरह से तैयार मिट्टी कि आवश्यकता होती है। किसान खरपतवारों को खेत से पहले बाहर निकाल दें और भूमि को समतल करने के लिए खेत की अच्छी तरह से जोताई करें।

बिजाई का समय

शहतूत की बिजाई आम तौर पर जुलाई अगस्त के महीने में की जाती है। किसान इसकी बिजाई के लिए जून जुलाई के महीने में बढ़िया ढंग से नर्सरी तैयार करें।

लालकिले से लाए थे पौधा

किसान अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि मार्च 2016 में वे दिल्ली भ्रमण के दौरान लाला किले से दो तरह के शहतूत के पौधे लाए थे। जिसमें एक है, लाल और दूसरा हरा शहतूत। दोनों की अपनी-अपनी खूबियां हैं। दोनों के फल काफी स्वादिष्ट हैं।

मिट्ठी: यह मिट्ठी की कई किस्मों जैसे दोमट से चिकनी, घनी उपजाऊ से समतल मिट्ठी, जिसका निकास प्रबंध बढ़िया हो और अच्छे जल निकास वाली और जिसमें पानी सोखने की क्षमता ज्यादा हो, में उगाया जाता है।

किस्म और पैदावार

एस-36: इसके पत्तों का आकार दिल के जैसा, मोटा और हल्के हरे रंग का होता है। इसकी औसतन पैदावार 15,000-18,000 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। पत्तों में उच्च नमी और पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

वी-1: यह किस्म 1997 में तैयार की गई थी। इसके पत्ते गहरे हरे रंग कर अंडाकार और चौड़े होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 20,000-24,000 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है।

सोयाबीन की उन्नत खेती से अन्नदाता होंगे आत्मनिर्भर

■ सोयाबीन फसल का पीली क्रांति में अहम योगदान

■ कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को दिए सुझाव आए सलाह

संवाददाता, टीकमगढ़

मध्यप्रदेश राज्य ने सोयाबीन फसलोत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसलिए मध्यप्रदेश को सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन फसल का पीली क्रांती में विशेष योगदान रहा है। सोयाबीन में प्रोटीन 40-45 फीसदी, तेल 20-22 फीसदी, कार्बोहाइड्रेट 20-21 प्रतिशत और 50 फीसदी मिनरल पाया जाता है। मप्र में सोयाबीन की औसतन उत्पादकता अन्य राज्यों से कम होने के कारणों में पाया गया कि किसान अभी भी उन्नत तकनीक को समय पर नहीं अपना रहे हैं। जिससे लागत अधिक और उत्पादन आशानुरूप नहीं मिल पा रही है। सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के लिए हल्की और दोमट भूमि उपयुक्त होती है। भूमि का पीच मान 6-5 से 7-5 के मध्य होना चाहिए। बारिश के पानी के निकास के लिए खेत में सहायक नालियां बनाकर मुख्य जल निकास की नाली में जोड़ना चाहिए।

भूमि की तैयारी: फसल को कीट व्याधियों से बचाने के लिए तीन वर्ष में एक बार गर्मी में गहरी जुताई जरूर करना चाहिए। इससे फफूंद व कीड़ों के अंडे, शंखी आदि नष्ट हो जाते हैं। मानसून आने के बाद ही खेत को 2-3 बार कल्टीवेटर से या एक बार रोटावेटर चलाकर खेत को कचरा रहित भुरभुरा तैयार कर लेते हैं। खेत को पाटा चलाकर समतलीकरण और भुरभुरा बना लेते हैं।

उन्नत किस्म: सोयाबीन की मुख्य उन्नत किस्मों में प्रमुख रूप से जेएस-95-60, जेएस-93-05,जेएस-20-34, जेएस-20-29, आरवीएस-2001-4, एनआरसी-37, जेएस-97-52, जेएस-20-69 और जेएस-20-98 शामिल हैं।

खाद और उर्वरक : मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतौर पर गोबर खाद 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर का किसान उपयोग करें। उर्वरक में नत्रजन 20 किलो, स्फुर 60 किलो, पोटाश 20 किलो और सल्फर 20 किलो प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। उपरोक्त पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए यूरिया (46 प्रतिशत एन) 44 किलो सिंगल सुपर फास्फेट (16 प्रतिशत पी), 375 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश (60 प्रतिशत के-) 33 किलो प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट के उपयोग से गंधक (सल्फर) की पूर्ति हो जाती है।

फसल की कटाई: सोयाबीन की फसल को 95 प्रतिशत फल्लियां पक जाएं और संपूर्ण पत्तियां खेत में गिर जाने तक कटाई श्रमिकों या हार्वेस्टर द्वारा कर ली जाए। गहाई के बाद उत्पादन को खलिहान में ठीक से जब तक सुखाएं कि दांत से दबाने पर कट की आवाज आना चाहिए। उसके बाद उत्पादन का भंडार ठीक से कर सुरक्षित रखें।

इनका कहना है

कालर रॉट रोग सोयाबीन की फसल की प्रारंभिक अवस्था में आता है। इससे पौधा भूमि की सतह पर गलना शुरू होकर पौधा मर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बोक्सीन 37.5 प्रतिशत और थायरम 37.5 प्रतिशत दो ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोवनी करें।

डॉ. बीएस किरार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि केंद्र, टीकमगढ़

सोयाबीन में पीला मोजेक बीमारी से पौधे पीला पड़ना शुरू हो जाते हैं और फल्लियां कम बनती हैं जिससे उत्पादन कम हो जाता है। बीज की दर से उपचरित कर बोवनी करें। फसल में रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ दें।

डॉ. आरके जायसवाल, प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, सीहोर

उन्नत खेती के लिए सोयाबीन की बोवनी कतारों में ही करना चाहिए। अधिक शाखा वाली किस्मों को 40 से 45 सेमी की दूरी पर बोना चाहिए। शीघ्र पकने व सीधी बढ़ने वाली किस्मों को 30 सेमी की दूरी पर बोवनी करना चाहिए।

डॉ. नेहा सिंह किरार, प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, सीहोर

सोयाबीन बारिश के सीजन की फसल होने के कारण सिंचाई की जरुरत नहीं पड़ती है। सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के लिए पुष्पावस्था से लेकर दाना भरने की अवस्था तक नमी रहना चाहिए।

डॉ. एचडी वर्मा, प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, सीहोर

तरबूज के दाम गिरे तो किसान ने पशु-पक्षियों के लिए भेज दिए ओंकारेश्वर

खंडवा। खेती से लाभ उठाने के लिए हर किसान जी तोड़ मेहनत करता है। गर्मी के सीजन में मेहनत कर तरबूज की फसल उगाई। उत्पादन तो उम्मीद के मुताबिक हुआ, लेकिन भाव नहीं मिले। थोक मंडी में यह तरबूज 8 रुपए किलो बिकता है। लेकिन दाम गिरकर 3 से 4 रुपए किलो पर आ गए हैं तो एक किसान ने पशु-पक्षियों के भोजन के लिए खेत से निकले सभी तरबूज ओंकारेश्वर भेज दिए। भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता सुभाष पटेल ने बताया गांव बावडिया काजी में किसान पवन साद ने दो एकड़ में तरबूज की फसल उगाई। उत्पादन अच्छा हुआ, लेकिन इस साल भाव नहीं मिले। किसान को जानकारी मिली कि ओंकारेश्वर को कोरोना कर्फ्यू के चलते पूरी तरह सील कर दिया गया है। जिसके चलते वहां गौवंश सहित बंदर आदि पशु-पक्षियों को भोजन के लाले पड़ गए हैं। ओंकारेश्वर स्थित कुछ आश्रमों से संपर्क किया और 10 टन तरबूज पशु-पक्षियों के भोजन के लिए ओंकारेश्वर भेज दिए।

बावडिया काजी के किसान को दो एकड़ में 10 टन मिला था उत्पादन

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रेस तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, इमामी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र.
संपर्क करें- 07554014144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)